

to co-operate with Nigeria in the establishment of small scale industries and ancillary industries. Apart from the items already identified by NSIC, domestic consumer items and metal cutting industry were also considered as industries in which India could offer assistance to Nigeria. Assistance in the training and orientation of Nigerian personnel in small scale industries was also offered.

SHRI R. P. GAEKWAD: Sir, in view of the fact that a lot of our nationals have gone there for their own betterment, is the Government thinking of giving them priority for setting up of the industries. If not, why this possibility has not been looked into?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): For international cooperation, we go to another country. It is a cooperation between us and the Government of that country when we negotiate.

As far as the Indian settlers are concern, in fact, the trend in international cooperation, more so in the case of India and developing countries, is that Indians settled there belong to those countries and they have been taking the maximum advantage of that. But, you would appreciate that we cannot bifurcate this. For example, in Nigeria because Indians settled there are Nigerians. International cooperation covers all the plans and they are discussed, negotiated and then submitted to us by them.

श्री प्रताप भागु शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय उद्योग-मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-नाइजीरिया संयुक्त कमीशन की जो बैठक हुई, उसमें लघु उद्योगों के आलावा मध्यम और बड़े उद्योगों की संभावना के बारे में भी विचार किया गया या नहीं ? इसके आलावा क्या नाइजीरिया में कुछ

उद्योग संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने के लिए भी दोनों देशों की सरकारें विचार कर रही हैं ?

श्री चरणजीत चानना : इंडो-नाइजीरियन कमीशन में जिन जिन मूख्य विषयों के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है व मैं आपको बता देना हूँ, उसमें छोटे और बड़े-दानों तरह के उद्योग आ जाते हैं ।

Agriculture and allied industries, Rice production, processing and milling; manufacture of simple farm tools and equipment; Agro-aviation; Agricultural extension; Fertilisers; post harvest technology; livestock, fisheries; Agro-based and food processing industry; Dairy development; Building materilas, engineering and transporation; Chemicals and...

MR. SPEAKER: That will do.

DR. KRUPASINDHU BHOI: I would like to know whether Government has provided any technical experts to that country for industrial development. If so, what are the numbers and categories? Secondly, apart from Nigeria which are the other countries which are interested to set-up industries in their countries with the help of our technicians?

SHRI CHARANJIT CHANANA: Sending of technical experts is, in fact, part of development of small industries in Nigeria. The other major countries where the international cooperation in the small scale sector is concerned are: Afghanistan, Nepal, Uganda, Tanzania, Indonesia, Zanzibar, Ghana, Zambia, Algeria, Phillipines, Sri Lanka, Kenya, Iran, Iraq, Syria, Mauratius...

MR. SPEAKER: That is enough.

इस ती में स्वतंत्रता सेनानो परामर्शदात्री समिति को बैठक

* 142. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित स्वतंत्रता सेनानो परामर्शदात्री

समिति को 18 जून, 1981 को दिल्ली में बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बैठक में लिए गये निर्णयों को मुद्दम बातें क्या हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

(b) The recommendations made in the meeting are given in the Statement attached.

Statement

RECOMMENDATIONS MADE BY THE NON-OFFICIAL ADVISORY COMMITTEE FOR ADVISING ON MATTERS PERTAINING TO IMPLEMENTATION OF SWATANTRATA SAINIK SAMMAN PENSION SCHEME IN ITS MEETING HELD ON 18-6-1981.

1. Extension of last prescribed date for receipt of applications for Samman Pension by six months from 31-7-1981 to 31-1-1982.

2. Admission of Samman Pension to persons who have undergone imprisonment in connection with Swaz Canal and Ambala Cantt. Cases from 1-8-1980, as a Special Case.

3. Admission of Samman Pension w.e.f 1-8-80 to persons who have suffered imprisonment in connection with C. I. H Mutiny and Egypt Mutiny Cases as a Special Case without reversal of the Government's approach and decision in these issues.

4. Acceptance of Kuka Movement (1871) as part of National Freedom Struggle.

5. Acceptance of Holwell Monument Removal Movement (1940) as part of National Liberation Movement.

6. Grant of pension to ex-INA women members of Rani of Jhansi

Regt. who fought on the War fronts. in relaxation of the provision of Pension Scheme.

7. Eligibility for Samman Pension of Children born to freedom fighter parents in jails or who remained with them in jails for qualifying periods, in relaxation of the provision of the Pension Scheme.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी मंत्री महोदय द्वारा जो जवाब दिया गया है उसमें 7 सिफारिशों की चर्चा की गई है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इन सातों सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और क्या कुछ और कटेगरी के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बचे हुए हैं, जिनके बारे में सरकार को तय करना अभी बाकी है। अगर यह बात है तो उनके बारे में सरकार कब तक फैसला करने का विचार रखती है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : उस में कई बातें ऐसी हैं जिन में पैसे की बात है। इसलिए फाइनेन्स मिनिस्ट्री को रेफर करना पड़ा है। उसकी कानकॉरेंस के बाद ही उसको तय किया जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री : आपने किसी सिफारिश को माना है या नहीं माना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : उस में फाइनेन्शियल इन्वाल्वमेंट है, इस लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को रेफर किया गया है।

श्री रामावतार शास्त्री : बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया था कि अभी जो छः महीने तक जेल में रहने की शर्त है उसे तीन महीने का दिया जाए। क्या इस बात पर भी विचार किया गया है ? जिन सेनानियों को गांधी इविन पैकट के बाद जेल से रिहा कर दिया गया था और जो छः महीने तक जेल में नहीं रहे थे क्या उन लोगों

को भी पेंशन देने के सिलसिले में विचार किया गया है? इन दोनों बातों के सम्बन्ध में विचार किया गया था क्या और अगर किया गया था तो सरकार की प्रतिक्रिया इस के बारे में क्या है?

श्री योगेश्वर मकवाना : विचार किया गया था लेकिन मैंने जैसे पहले बताया है, उन की सिफारिशों में फ्राइनेल्सियल इनवाल्ड-मैंट है इसलिए फ्राइनेल्स मिनिस्ट्री को रेफर किया है। उसका कन्कलरेंस मिलने के बाद उस पर कुछ किया जा सकता है।

श्री रामाक्षर शास्त्री : मैंने दो अलग अलग सवाल उठाए हैं। गांधी इयिन पैक्ट के बाद जिन लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया था उनके बारे में आपकी राय क्या है? अभी आप पांच महीने ऐसे लोग जो जेल में रह जाते हैं उनको देते हैं लेकिन तीन महीने और चार महीने जो रहे हैं उनके बारे में भी क्या आपने फ्राइनेल्स मिनिस्ट्री को रेफर किया है? मैंने यह भी कहा है कि छः महीने के बदले तीन महीने कर दिया जाए और उन लोगों को भी पेंशन दी जाए, क्या इस पर आप राजी है? यह पालिसि मेटर है।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : शास्त्री जी खुद एडवाइजरी कमेटी के मੈम्बर है। इन बातों पर वहाँ गौर किया गया था। रिले-केशन पंद्रह दिन का छः महीने की सीमा में कर दिया जाए यह जो सिफारिश की गई थी अभी उस पर अमल होने वाला है। जहाँ तक स्ट्रियों और हरिजनों का सवाल है उसको हमने पहले ही छः महीने के बजाय तीन महीने तक कर दिया है ताकि उनको पेंशन मिल सके। कुछ संस्थायें ऐसी हैं जिन को हम इस कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं लेकिन उनका कांट्रीब्यूशन हमारी आजादी की लड़ाई में हमारा सहायक रहा है, हमारी सहायता वे करती रही हैं इस ख्याल से उनको

फ्रीडम फाइटर वाला सम्मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी माली मदद करने के लिए उनको पेंशन दी जा सकेगी। तामपत्र उनको नहीं दिए जाएंगे लेकिन कुछ रिथाबलें उनको दी जा सकेंगी—वे जो फ्रीडम फाइटरों को दी जाती हैं—उनको दी जा सकेंगी और रिकगनाइज उनको कर लिया जाएगा कि उनकी भी खिदमत हुई है।

SHRI B. K. NAIR: May I know whether the hon. Minister is aware that in the last few weeks just preceding the last day of application (namely, 31st July, 1981) certain political parties in Kerala belonging to the ruling party there, were carrying on a hectic campaign to canvass tens of thousands of applications from all bogus freedom-fighters for building up their own party funds? If so, would he ensure that these applications would be properly screened and a suitable machinery for screening set up for the purpose?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: There are some complaints about the bogus applications received from Kerala and Bihar and other parts of the country also and we are scrutinising them. In cases where these are found to be bogus, we suspend the grant of pension.

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Is it a fact that in Assam State, there are much political sufferers who are getting political pension from the State? These persons have been imprisoned for six months and over and they have been getting pension from the State, but they are not getting anything from the Centre. May I know whether this is a fact? If so, what is the reason for the same; and what do you propose to do in the matter?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: In cases where applications have been received by the Centre, we have sanctioned them if all the requirements are fulfilled.